(e) and (d) Allocation to the State Plan is made by the Planning Commission as block loans and block grants and sectorwise allocation are decided by the Slate Governments. Govt, of India has not received any proposal from Government of Gujarat requesting for increase in the allocation for the Hood sector.

World Bank Funds to Orissa

926. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the instance of World Bank, Government have instructed to raise the water rate in Orissa by 50%;

(b) what are the details of the amount released to Orissa from the World Bank with the terms and conditions, thereof;

(c) whether any monitoring is being conducted by Government regarding the proper utilisation of funds released from time to time to the State; and

(d) if so, what is the report of such monitoring?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SIS RAM OLA): (a) Under Schedule 2 (Implementation Program) of the Project Agreement for Orissa Water Resources Consolidation Project between I.D.A. and State of Orissa, it is provided that "Orissa shall take all necessary measures to achieve recovery from users of the full cost of operation and maintenance of the combined water sector as follows (i) 50% by March 31, 1997; (ii) 80% by March 31, 1998; and (iii) 100% by March 31, 2000. Orissa shall thereafter maintain such full cost recovery".

(b) An amount of US$ 51.76 Million has been utilised by the Government of Orissa up to October, 1997 on the above project, leaving a balance of US$218.81.

(c) and (d) Regular physical and Financial progress of the project is being monitored by Central Water Commission and as on date the progress of the project is satisfactory.

उत्तरी बिहार में पानी का अभाव

927. **श्री नागमणि :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की उदासीनता के कारण उत्तरी बिहार में पानी के जमाव की समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है, और

(ख) इस संबंध में बिहार सरकार से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश रामा ओला) : (क) बिहार सरकार ने उत्तर बिहार की जल जमाव की समस्या के विस्तार का अनुमान लगाया है । बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर बिहार में लगभग 9.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र जल जमाव से प्रभावितहै। (ख) बिहार सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में अब तक जल निकास संबंधी अलग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, पूर्वी कोसी नहर परियोजना फेज II और गण्डक परियोजना फेस II के संबधं में बिहार सरकार से सिंचाई पर दो प्रस्तावों प्राप्त हुए थे इसमें उत्तर बिहार में जल निकास के पहलु भी शमिल है । बिहार सरकार द्वारा एक वर्ष से अधिक भी शामिल है । बिहार सरकारा द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण इन परियोजनाओं को फरवरी, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग की परियोजनाओं की लंबित सूची से निकाल दिया गया था ।

बिहार में उथला नलकूप परियोजना

928. **श्री नागमणि :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करोगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई गैर-सरकारी कार्यक्रम के अतंर्गत उथला नलकूप परियोजना सरकार के पास लंबित पड़ी है ।

(ख) यदि हां, तो उपुर्यक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और यह कब प्राप्त हुई थी, और

(ग) इस संबधं में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) (i) बिहार के ताल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 25850 उथल नलकूपों के निर्माण की 22.23 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट बिहार सरकार से मार्च, 1997 में कृषि मंत्रालय में